- (क) क्या खादी तथा प्रामीखीन श्रामीय का विचार 'पाम कोला' नामक शीतल पेय बडी माला में सप्लाई करने का है क्योंकि इसे काफी लोकप्रियता मिली है :
- (खा) यदि हां, तो इस समय इसक मासिक उत्पादन (बोतली) में कितना है ;
 - (ग) वर्ष 1978-79 में इसका उत-दन बढ़ा कर कितना किया जायेगा. भीर
- (घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है।

उद्योग मजालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शामा मयती): (क) से (घ). तमिलनाड राज्य खादी एवम ग्रामीण उद्योग बोर्ड के श्रधीन कार्य करने वाली तमिलनाड स्टेट पाम-गृड फेडरेशन ने पाम कोला पेय का नमुना तयार किया है। तमिलनाड स्टेट पाम-गड फेडरेशन खादी एवम ग्रामीण उद्योग भायोग के परामर्श से वित्तीय एवम इसे चालु करने संबधी ब्यौरे तैयार किए जा रहे है । फैंड-रेशन का प्रस्ताव है कि जनता तक पाम कोला पहुंचाने के लिए वर्ष 1978-79 में दो तैयार करने वाले एकक स्थापित किए जाएं जिनमें से एक मद्रास में तथा दूसरा नई दिल्ली में स्थापित किया जाए । धनमान है कि प्रत्येक पाम कोला एकक के लिए 5 लाख रुपए के निवेश की शावस्यकता पडेगी तथा वह एकक 2.5 लाख बोतल प्रति माह का उत्पादन कर सकेगा। इन दो एककां का भीर श्रधिक विस्तार इनकी वाणिज्यिक सफलता पर निर्भर करेगा।

All India Cadre for Hindi Translation Service

7451. SHRI RAJKESHAR SINGH: SHRI RAMANAND TIWARY: SHRI RAM JIWAN SINGH:

Will the Minister of HOME AF-FAIRS be pleased to state:

- (a) whether Government are contemplating to evolve an All India cadre for Hindi Translation services
 - (b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN . THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) No Sir, the Government are not contemplating to evolve an All India cadre for Hindi Translation Service but they are contemplating to bring the Hindi posts in the Central Secretariat under one service.

(b) Does not arise.

Rationalisation of Coal Industry

7452. SHRI SARAT KAR: Will the Minister of ENERGY be pleased to

- (a) whether Government propose to rationalise the administrative set up of the nationalised coal industry to ensure effective functioning; and
 - (b) if so, the main features thereof?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) and (b). The administrative set up of the nationalised coal industry was reorganised in July, 1977 with a view to ensuring its effective functioning. The roles of the holding company and companies were of the subsidiary redefined with a view to providing for more decentralisation in day to day matters. The delegation of powers to various authorities has been adopted by the coal companies. The performance of the coal companies after this re-organisation is being reviewed by the Government periodically. If and when need arises further change in the administrative set up of the coal companies will be undertaken.